



Wed- 29 Jul - 2026

Year - 01

Issue - 114

Page - 01

Rs. - 5

www.azadvaani.com

मान सरकार ने शिक्षा और बिजली विभागों को कर्मचारियों की मांगों के समाधान में तेजी लाने



चंडीगढ़, 29 जुलाई: पंजाब के वित्त मंत्री एवं कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट उप-कमेटी के चेयरमैन हरपाल सिंह चीमा ने शिक्षा विभाग की सात और बिजली विभाग की दो यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर अधिकारियों को लंबित मांगों के समाधान की प्रक्रिया तेज करने के निर्देश दिए।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस की मौजूदगी में 3704 अध्यापक यूनियन, ईटीटी टेट पास टीचर्स एसोसिएशन, यूनाइटेड फिजिकल एजुकेशन यूनियन, पुनर्बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन और आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापकों की मांगों पर विस्तार से चर्चा हुई। चीमा ने अधिकारियों को यूनियनों के साथ संयुक्त बैठक कर जायज मांगों के समाधान के लिए प्रस्ताव तैयार करने तथा 250 आर्ट एंड क्राफ्ट पदों की भर्ती का समाधान निकालने के निर्देश दिए।

विजिलेंस ब्यूरो ने शिक्षा विभाग के क्लर्क को ₹10,000 रिश्त लेते रंगे हाथों दबोचा



चंडीगढ़, 29 जुलाई: पंजाब विजिलेंस ब्यूरो ने भ्रष्टाचार विरोधी अभियान के तहत ब्लॉक प्राइमरी शिक्षा कार्यालय (बीपीईओ), हाजीपुर, जिला होशियारपुर में तैनात क्लर्क गगन को ₹10,000 की रिश्त लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। कार्रवाई गांव सुल्तानपुर, जिला मालेरकोटला के एक निवासी की शिकायत के आधार पर की गई।

शिकायतकर्ता की पत्नी सरकारी एलीमेंट्री स्कूल, गांव सहोरा में ईटीटी अध्यापिका हैं। उनकी चाइल्ड केयर लीव स्वीकृत कराने के लिए शिकायतकर्ता बीपीईओ कार्यालय पहुंचा, जहां आरोपी क्लर्क ने बाद में फोन कर अवकाश मंजूर करवाने के बदले ₹10,000 रिश्त की मांग की। शिकायतकर्ता ने रिश्त मांगने की बातचीत रिकॉर्ड कर विजिलेंस ब्यूरो, रेंज जालंधर से संपर्क किया।

शिकायत की पृष्ठ के बाद विजिलेंस टीम ने जाल बिछाकर दो सरकारी गवाहों की मौजूदगी में आरोपी को शिकायतकर्ता से ₹10,000 की रिश्त लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। मौके से रिश्त की राशि भी बरामद कर ली गई।

‘फोटो वीडियो एक्सपो 2026’ का भव्य समापन, किसान भवन में दूसरे दिन उमड़ा फोटोग्राफरों और कंटेंट क्रिएटर्स का सैलाब



चंडीगढ़, 29 जुलाई 2026: पंजाब सरकार ने शिक्षा और बिजली विभागों के कर्मचारियों की लंबित मांगों के समाधान की प्रक्रिया को तेज करने का फैसला किया है। वित्त मंत्री एवं कर्मचारियों के मुद्दों के समाधान के लिए गठित कैबिनेट उप-समिति के अध्यक्ष हरपाल सिंह चीमा ने बुधवार को शिक्षा विभाग की सात और बिजली विभाग की दो कर्मचारी यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक कर संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई में तेजी लाने के निर्देश दिए।

बैठकों के दौरान हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार भर्ती, नियमितीकरण और कर्मचारियों से जुड़े सेवा संबंधी मामलों का समयबद्ध समाधान करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सेवा संबंधी मामलों की समीक्षा के लिए गठित समिति तथा वित्तीय मामलों की जांच कर रही वित्त समिति अपनी प्रक्रिया में तेजी लाए, ताकि कर्मचारियों के हित में जल्द से जल्द ठोस और लागू किए जा सकने वाले प्रस्ताव तैयार किए जा सकें।

शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस की मौजूदगी में हुई बैठक में 3704 अध्यापक यूनियन की विभिन्न मांगों पर विस्तार से चर्चा की गई। वित्त मंत्री ने 9 जुलाई को गठित उच्च स्तरीय समिति, जिसमें वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय के अधिकारी और यूनियन प्रतिनिधि शामिल हैं, को अपनी औपचारिक सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

ईटीटी टेट पास टीचर्स एसोसिएशन द्वारा उठाए गए वित्तीय और सेवा संबंधी मुद्दों पर भी गंभीर विचार-विमर्श किया गया। हरपाल सिंह चीमा ने वित्त और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यूनियन प्रतिनिधियों के साथ तुरंत संयुक्त बैठक आयोजित करने और सभी जायज मांगों के समाधान के लिए व्यवहारिक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा यूनाइटेड फिजिकल एजुकेशन यूनियन तथा पुनर्बहाल कच्चे अध्यापक यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ भी अलग-अलग बैठकें हुईं। वित्त मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि इन यूनियनों की लंबित मांगों के समाधान के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी

लाई जाए, ताकि कर्मचारियों को जल्द राहत मिल सके।

आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापकों के 250 पदों पर भर्ती के मुद्दे पर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले का प्रभावी और स्थायी समाधान निकालने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने विभिन्न आर्ट एंड क्राफ्ट यूनियनों से आपसी मतभेद समाप्त कर एक संयुक्त मांगपत्र प्रस्तुत करने की अपील की, जिससे सरकार के लिए निर्णय लेना आसान हो और भर्ती प्रक्रिया को गति मिल सके।

बिजली विभाग से संबंधित बैठकों में पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं सरकार के समक्ष रखीं। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभागीय अनुबंध के तहत लाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल के लागू होने से आउटसोर्स कर्मचारियों की अधिकांश समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाएगा।

शिक्षा और बिजली विभागों के कर्मचारियों की मांगों के समाधान में तेजी लाएगी मान सरकार, हरपाल सिंह चीमा ने दिए सख्त निर्देश



स्तरीय समिति, जिसमें वित्त विभाग, कार्मिक विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग, महाधिवक्ता कार्यालय के अधिकारी और यूनियन प्रतिनिधि शामिल हैं, को अपनी औपचारिक सिफारिशें शीघ्र प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।

ईटीटी टेट पास टीचर्स एसोसिएशन द्वारा उठाए गए वित्तीय और सेवा संबंधी मुद्दों पर भी गंभीर विचार-विमर्श किया गया। हरपाल सिंह चीमा ने वित्त और स्कूल शिक्षा विभाग के अधिकारियों को यूनियन प्रतिनिधियों के साथ तुरंत संयुक्त बैठक आयोजित करने और सभी जायज मांगों के समाधान के लिए व्यवहारिक प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए।

इसके अलावा यूनाइटेड फिजिकल एजुकेशन यूनियन

के साथ भी अलग-अलग बैठकें हुईं। वित्त मंत्री ने स्कूल शिक्षा विभाग को निर्देश दिया कि इन यूनियनों की लंबित मांगों के समाधान के लिए प्रशासनिक प्रक्रिया में तेजी लाई जाए, ताकि कर्मचारियों को जल्द राहत मिल सके।

आर्ट एंड क्राफ्ट अध्यापकों के 250 पदों पर भर्ती के मुद्दे पर हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि राज्य सरकार इस मामले का प्रभावी और स्थायी समाधान निकालने के लिए सक्रिय रूप से कार्य कर रही है। उन्होंने विभिन्न आर्ट एंड क्राफ्ट यूनियनों से आपसी मतभेद समाप्त कर एक संयुक्त मांगपत्र प्रस्तुत करने की अपील की, जिससे सरकार के लिए निर्णय लेना आसान हो और भर्ती प्रक्रिया को गति मिल सके।

बिजली विभाग से संबंधित बैठकों में पीएसपीसीएल और पीएसटीसीएल के कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों की समन्वय समिति के प्रतिनिधियों ने अपनी समस्याएं सरकार के समक्ष रखीं। इस पर वित्त मंत्री ने कहा कि राज्य सरकार आउटसोर्स कर्मचारियों को सीधे विभागीय अनुबंध के तहत लाने की दिशा में कार्य कर रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि इस पहल के लागू होने से आउटसोर्स कर्मचारियों की अधिकांश समस्याओं का स्वतः समाधान हो जाएगा।

वैट बकाया वसूली में पंजाब सरकार की बड़ी कार्रवाई, संपत्ति नीलामी से ₹1.21 करोड़ वसूल; 31 जुलाई तक ओटीएस योजना का लाभ उठाने की अपील



चंडीगढ़, 29 जुलाई 2026: पंजाब सरकार ने वैल्यू एडेड टैक्स (वैट) के लंबित बकायों की वसूली के लिए चलाए जा रहे अभियान में तेजी लाते हुए पटियाला जिले में संपत्तियों की नीलामी के माध्यम से बड़ी सफलता हासिल की है। राज्य के वित्त, आबकारी एवं कर मंत्री एडवोकेट हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि विभाग ने हाल ही में संपत्ति नीलामी के जरिए 1.21 करोड़ रुपये की वसूली की है, जबकि एक अन्य मामले में एकमुश्त निपटान (ओटीएस) योजना के तहत 18.46 लाख रुपये तत्काल जमा करवाए गए। उन्होंने सभी पात्र बकायेदार डीलरों से 31 जुलाई 2026 से पहले ओटीएस योजना का लाभ उठाकर अपने पुराने कर बकायों का निपटारा करने की अपील की है।

हरपाल सिंह चीमा ने कहा कि सरकार का उद्देश्य व्यापारियों को स्वेच्छा से बकाया चुकाने का अवसर देना है, लेकिन निर्धारित समय सीमा के बाद किसी भी प्रकार की रियायत नहीं दी जाएगी। उन्होंने स्पष्ट किया कि 31 जुलाई के बाद ओटीएस योजना समाप्त हो जाएगी और जिन डीलरों ने अपने बकाए का भुगतान नहीं किया, उनके खिलाफ संपत्ति कुर्की, सार्वजनिक नीलामी और अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वित्त मंत्री ने बताया कि पटियाला जिले के मैसर्स गुरुजी फीड्स, राजपुरा पर 57.78 लाख रुपये का वैट बकाया था। विभाग ने उसकी संपत्ति की नीलामी 27 जुलाई 2026 को निर्धारित की थी। नीलामी प्रक्रिया शुरू होते ही संबंधित डीलर ने ओटीएस योजना के तहत राहत का लाभ उठाते हुए 18.46 लाख रुपये जमा कर अपने मामले का निपटारा कर लिया। उन्होंने कहा कि यह उदाहरण दर्शाता है कि सरकार द्वारा लाई गई ओटीएस योजना पात्र व्यापारियों को बकाया निपटाने का सुनहरा अवसर प्रदान करती है और समय रहते इसका लाभ उठाकर वे अपनी संपत्ति की कुर्की और जबरन बिक्री जैसी कार्रवाई से बच सकते हैं।

एक अन्य महत्वपूर्ण कार्रवाई का उल्लेख करते हुए हरपाल सिंह चीमा ने बताया कि कर विभाग ने मैसर्स समाना रोलर फ्लोर मिल लिमिटेड की संपत्ति की सफलतापूर्वक नीलामी कर 1.21 करोड़ रुपये की वसूली की। यह राशि संपत्ति की 74.31 लाख रुपये की आरक्षित कीमत से लगभग 46.69 लाख रुपये अधिक रही।

Innovation & Excellence

Advertisement

Are you looking for a reliable EMAIL SERVICE PROVIDER?

Choose the best suitable plan for your business from **SquareNet**

Secure & Reliable

Professional Email

Cloud Integration

24/7 Expert Support

Scalable for Every Business

Empower Your Business with Secure, Professional & Scalable Email Solutions

SQUARENET INDIA PRIVATE LIMITED
C-6, Sebiz Square, IT Park, Sector 67,
Mohali 160062, Punjab India

www.squarenetindia.com

mail@squarenetsolutions.com

+91-904-101-2541
[PRI LINE]

Visit Us: www.azadvaani.com

For Enquiry Call: +91-90414-88440

herbegy™

Think pure think herbal

PREMIUM SPICES RANGE

Pure Spice. Rich Flavour.



PURE | AROMATIC | PREMIUM QUALITY

Advertisement

For Dealer Inquiry Contact:

727-515-0015